सुधार के प्रतिफल वितरित करना

लेखक-आशिमा गोयल (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) एवं प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

2 फरवरी, 2019

"विस्तृत बजट राजकोषीय समेकन, कर सुधार और सब्सिडी के सुव्यवस्थित वितरण के फल को दर्शाता है।"

चूंकि इस साल आम चुनाव से पहले बजट 2019 आखिरी है, इसलिए सरकार के प्रदर्शन का आकलन होने की उम्मीद अपेक्षित था। इस बात पर बहस चल रही थी कि क्या बजट में सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाने की घोषणा की जाएगी, जिससे कि वे चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार को इसे लागू करने के लिए बाध्य कर सके।

राजकोषीय समेकन, कर सुधार, सब्सिडी का अधिक कुशल वितरण, और पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी में वृद्धि ने करदाताओं को पुरस्कृत करने के साथ-साथ राजकोषीय समेकन में कोई समझौता किए बिना संकट में किसानों के लिए राहत उपाय की घोषणा करने के लिए जगह बनाई है। यह उचित है कि कई सुधारों को लागू करने और कठिन कार्रवाई करने वाली इस सरकार को उस सुधार के कुछ पुरस्कार भी वितरित करने चाहिए।

उच्च विकास का पुरस्कार

सरकार से यह पूछा जा सकता है कि किसानों को 20,000-75,000 करोड़ रुपय का भुगतान और राजकोषीय घाटे पर मामूली प्रभाव के साथ कर लाभ कैसे दिया जा सकता है। लेकिन एक बड़े आकार की अर्थव्यवस्था घाटे की अनुपात और उधार आवश्यकताओं में केवल एक छोटी वृद्धि के साथ बड़ी पूर्ण मात्रा में खर्च का जोखिम उठा सकती है। तथ्य यह है कि भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और औपचारिकता की दिशा में उठाय गए अन्य कदमों ने कर आधार में वृद्धि की और इसी कारण से कर दरों में कटौती की जा सकी है। फिर यह उचित है कि आम आदमी, जो सुधार की कुछ लागतों से ऊब चुका है, को अब इनकी सफलता से लाभ मिले। यह व्यापक आधार और कम दरों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए अच्छी आर्थिक समझ रखता है। कर की प्राप्ति सकल घरेलू उत्पाद के 10% से बढ़ी है - जो एक एक स्तर था जिस पर उन्होंने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद कर कटौती के बाद से 12% तक स्थिर कर दिया था। हालांकि जीएसटी अभी तक अप्रत्यक्ष कर अनुपात 5.5% से अधिक नहीं बढ़ा है, लेकिन भविष्य में ऐसा होने की संभावना है क्योंकि यह स्थिर है। इस साल किसानों की जीडीपी में केवल 0.4% की कटौती हुई है और कर अनुपात में 0.3% की वृद्धि हुई है।

जेएएम (या जन धन-आधार-मोबाइल) सुधारों का एक अन्य प्रमुख समूह है, जो छोटे खर्च को सामाजिक कल्याण पर बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम बनाता है। देश के माध्यम से खोले गए जन-धन बैंक खाते और आधार डेटा आधार किसानों के लिए लागत प्रभावी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) संभव बनाते हैं।

कम मुद्रास्फीति के पुरस्कार

महंगाई कम होने और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आने पर किसानों को धन हस्तांतरण के लिए राजकोषीय घाटे में मामूली वृद्धि से व्यापक आर्थिक स्थिरता को खतरा नहीं है। वास्तव में वे कीमतों को स्थिर करने में मदद करने की संभावना रखते हैं ताकि किसान अगले फसल चक्र में उत्पादन में कटौती न करें।

इसके अलावा, इस वर्ष, राजस्व घाटा बनाए रखा गया है, प्राथमिक घाटा कम किया गया है और पूंजी खाते पर खर्च बढ़ाया गया है। सरकारी व्यय की बेहतर गुणवत्ता के साथ-साथ जीएसटी कर में कटौती, अंतर-राज्य व्यापार में बाधाओं में कमी और नरम वस्तु की कीमतें मुद्रास्फीति को कम रखेंगी।

बजट के अनुसार, राजमार्ग 27 किमी प्रति दिन की दर से बनाए जा रहे हैं जो भारत को दुनिया का सबसे तेज निर्माणकर्ता बनाता है। रेलवे सुरक्षा में सुधार हुआ है। बजट की तारीख को पहले वर्ष में शिफ्ट करने और पहली छमाही में खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामस्वरूप इस वर्ष सेक्टोरल खर्च के लक्ष्य की बेहतर उपलब्धि हुई है।

सरकारी उधारी

सरकारी उधारी का आकार बाजार के अनुमान से बड़ा है और इसने सरकारी प्रतिभूतियां दरों को बढ़ा दिया है। सकल उधारी में वृद्धि उच्च ऋणमुक्ति के कारण होती है लेकिन शुद्ध उधारी पिछले साल के समान है। उस वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों में तेज वृद्धि हुई थी। परिणामस्वरूप, जीडीपी के अनुपात में ब्याज भुगतान बजट द्वारा अनुमान किये गये 3 के मुकाबले 3.2 हो गया।

लेकिन जीडीपी का 3.4% एक बड़ा राजकोषीय घाटा नहीं है और बाजार की स्थिति इस साल सरकार के उधार के आंकड़ों से

अधिक सहायक होने की संभावना है। सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय दर वृद्धि चरम पर है, यू.एस. ने संकेत दिया कि कोई और वृद्धि नहीं होगी; इसकी बैलेंस शीट बनाए रखने की संभावना है। घरेलू बाजार में 6% की मौजूदा कैप तक सरकारी प्रतिभूतियों की मांग पैदा करते हुए उभरते बाजार प्रवाह में वृद्धि हुई है। तेल की कीमतें विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजारों में लौटने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। चूंकि वैश्विक विकास धीमा है, इसलिए इसके 2017 जैसा बढ़ने की संभावना नहीं है।भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार संचालन (ओएमओ) के लिए अधिक जगह होगी जो ऋण बाजार का समर्थन करते हैं। ब्याज दरों में नरमी से बैंक सरकारी प्रतिभूतियों पर नियंत्रण बनाने में मददगार साबित होंगे।

जब अंतर्राष्ट्रीय मांग धीमी हो रही है, तो घरेलू मांग को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसलिए, कर कटौती, किसानों को अधिक आय और आवास की मांग में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं, जो तनाव में रही हैं, सभी उपयुक्त हैं।

जबकि पूंजीगत व्यय में बजटीय योगदान जीडीपी के लगभग 1.6% पर है, आंतरिक और अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों में वृद्धि होगी, जो अब सकल बजटीय समर्थन से बड़ा है। लेकिन सार्वजनिक उद्यमों को आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने और उनका उपयोग करने में सक्षम होना होगा। यह सरकार पर दक्षता, बाजार व्यवहार्यता और कम निर्भरता का एक स्वस्थ संकेत है। यहां तक कि निजी निवेश कम होने पर निवेश के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐसे उद्यमों द्वारा बाजार उधार, निजी निवेश में भीड़ के बजाय (भीड़ से बाहर) होने की संभावना है। यह मांग बढ़ाएगा जो अधिक निजी निवेश को प्रेरित करेगा।

दक्षता में सुधार

अगली सरकार को बाध्य करने के मुद्दे पर वापस आते हुए, चुनाव के बाद, यह आवश्यक है कि विकास लाभों का बंटवारा उन तरीकों से किया जाए जो विकास को बनाए रखें, विकृतियों को कम करें और विकास में भाग लेने की क्षमताओं में सुधार करें।
बजट में लेन-देन की लागत को कम करने और अनुपालन प्रोत्साहन में सुधार करने का प्रयास जारी है। स्टांप ड्यूटी संशोधन जो केवल एक लेनदेन पर कर लगाना चाहते हैं, जो राज्य सरकारों के साथ साझा किया जाएगा और खरीददार ग्राहक के अधिवास के आधार पर है, एक प्रमुख बाजार में अड़चन को कम करेगा, लेनदेन को बढ़ाएगा और देश को एक प्रभावी बाजार बनने की ओर ले जाएगा।
भारत में एक बड़ा बदलाव करना थोडा मुश्किल है। समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन लाभ या पुरस्कार दिखाई देने लगे हैं, इसलिए हमे इसका स्वागत करना चाहिए।

GS World टीम...

प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव

संदर्भ

- 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट।
- मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत।
- मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
- बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।
- आयकर की वर्तमान दरें जारी रहेंगी।
- अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट।
- आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा।
- किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव।
- पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा।
- सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
- बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।

राजकोषीय कार्यक्रम

- वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत।
- राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य 2020-21 तक हासिल किया जाएगा।
- राजकोषीय घाटे को 2018-19 आरई में घटाकर 3.4 प्रतिशत तक लाया जाएगा, जो 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत था।
- वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा।
- वर्ष 2019-20 के लिए पूंजीगत व्यय 3,36,292 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए आवंटन वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3,27,679 करोड़ रुपये होगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए वर्ष 2019-20 में आवंटन करीब 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38,572 करोड़ रुपये किया गया।
- एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के लिए आवंटन 18 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 27,584 करोड़ रुपये किया गया।

अर्थव्यवस्था

वर्ष 2014-19 के दौरान

- भारत ने पिछले पांच वर्षों के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर सार्वभौगिक पहचान बनाई।
- 2013-14 के 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।
- किसी भी अन्य सरकार की तुलना में औसत मुद्रास्फीति घटकर 4.6 प्रतिशत पर पहुंची।
- दिसंबर 2018 में मुद्रास्फीति सिर्फ 2.19 प्रतिशत पर पहुंची।
- 7 वर्ष पूर्व करीब 6 प्रतिशत की उच्च दर से 2018-19 में वित्तीय घाटा घटकर 4.6 प्रतिशत तक पहुंचा।
- सीएडी के 6 वर्ष पहले की उच्च 5.6 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के मात्र 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है।
- पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत ने 239 बिलियन डॉलर के व्यापक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 2019 के बजट में बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।
2. बजट 2019 में प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव में 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट प्रदान की गयी।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements

1. In the Budget of 2019, rebate on the estimated rental on the income tax on the unsold property has been proposed to incerase from one year to two year.

2. In the Budget 2019, in the proposal regarding the income tax, income upto Rs 5 lakh has been exempted.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 Nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'विस्तृत बजट' राजकोषीय समेकन, कर सुधार और सब्सिडी के सुव्यवस्थित वितरण के प्रतिफल को दर्शाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. 'Detailed Budget indicates rewards of the fiscal inclusion, tax reform and systematic distribution of subsidy. Do you agree with this statement? Discuss.

(250 Words)

नोट : 1 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।